तिब्बत देश

ओलंपिक मशाल पर आखिर राजनीति क्यों हुई ?

ओलंपिक मशाल की ग्रीस से चीन तक की विश्व यात्रा को लेकर पिछले दिनों जैसा अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय विवाद और हंगामा हुआ उसे देखकर बीजिंस सरकार बार–बार बौखलाकर यह आरोप लगा रही थी कि ओलंपिक को लेकर राजनीति की जा रही है। यह आरोप एक ऐसी सरकार लगा रही थी जो खुद धरती की किसी भी चीज को एक खास तरह के दकियानूसी राजनीतिक नजरिए से परे हटकर देख नहीं पाती। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश था जहां से होकर गुजरने वाली ओलंपिक मशाल के रास्ते में मानवाधिकार संगठनों और तिब्बत समर्थक संगठनों ने रोड़े न अटकाए हों। ग्रीस से लेकर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, भारत और जापान समेत लगभग हर देश में चीन सरकार के खिलाफ इतने तीखे प्रदर्शन हुए कि ओलंपिक आयोजकों और स्थानीय सरकारों को मजबूर होकर बार–बार ओलंपिक मशाल का रास्ता छोटा करना पड़ा। कई देशों में प्रदर्शनकारियों ने मशाल को छीनने या बुझाने में सफलता पायी।

हर जगह प्रदर्शनकारियों की शिकायत थी कि चीन की जनता के मानवाधिकारों को कुचलने वाली और तिब्बत जैसे कई देशों पर जबरन कब्जा जमाने वाली चीन सरकार को ओलंपिक आयोजित करने जैसा महान सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। उनका आरोप था कि जिस देश की सरकार अपने यहां नागरिकों को धार्मिक आजादी के बजाए जेल भेजती हो, अपने हजारों युवाओं को मुंह खोलने पर फौजी टैंकों के नीचे कुचलने से न झिझकती हो, और तिब्बत, सिंकियांग और भीतर मंगोलिया जैसे उपनिवेशों में नरसंहार और सांस्कृतिक संहार की दोषी हो, वैसे देश को ओलंपिक खेलों के आयोजन का सम्मान नहीं दिया जा सकता। लेकिन अपने आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक ताकत के बूते पर चीन सरकार ओलंपिक का सेहरा बांधने में कामयाब हो ही गई। मगर ओलंपिक मशाल के मामले में उसकी टक्कर सरकारों के बजाए मानवाधिकार संगठनों से थी।

हर तरह की चीनी कोशिशों के बावजूद शायद ही कोई ऐसा देश था जहां आयोजकों ने इस विरोध से डरकर मशाल की दौड़ को किलोमीटरों से घटाकर महज कुछ मीटरों की रस्म अदायगी तक न सीमित कर दिया हो। हालत यहां तक पहुंच गई कि चीन सरकार ने ओलंपिक की वर्दी में अपने सैनिकों और खुफिया एजेंटों को इन देशों में मशाल थामकर दौड़ने और उसके आसपास सुरक्षा घेरा बांधने पर लगा दिया। ब्रिटेन में तो इन चीनी एजेंटों ने ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को धक्के मारकर रैली से बाहर धकेलने जैसी उजड्डता दिखा दी।

कुल मिलाकर चीन सरकार ने बीजिंग ओलंपिक की मशाल को अपने लिए इज्जत का इतना बड़ा सवाल बना दिया मानो यह कोई खेलों की मशाल न होकर चीनी साम्राज्य का अश्वमेघ घोड़ा हो। चीन के इस दादागीरी वाले नजरिये का कई सरकारों ने विरोध किया और अपने देश में चीनी एजेंटों को हाशिए पर रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन चीनी इशारों पर नाचने वाले पाकिस्तान जैसे देश भी थे जिन्होंने चीन सरकार की पूरी जी हजूरी तो की लेकिन उसके बाद भी सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) के उइगुर स्वतंत्रता सग्रामियों के डर के मारे मशाल का रास्ता हास्यास्पद हद तक छोटा कर दिया। भारत में भी चीन को खुश करने पर तुली हुई सरकार के चेहरे पर ऐसा आतंक छाया रहा कि उसने डर के मारे पूरी मशाल यात्रा को न सिर्फ एक छोटे से रास्ते तक सीमित कर दिया बल्कि खिलाड़ियों के बजाए इसे पुलिस और फौज की वर्दियों के तमाशे में बदल दिया। इसी पर दुख व्यक्त करते हुए सुश्री किरण बेदी जैसे कई सम्मानित लोगों ने 'आई सी यू के भीतर' होने वाली इस परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जापान में तो उस मंदिर ने भी मशाल को अपने यहां प्रवेश करने से मना कर दिया जहां से इसकी दौड़ शुरू होनी थी। ताइवान ने भी मशाल की दौड़ को अपने यहां आयोजित करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि चीन सरकार चाहती थी कि दौड़ में ताइवान को 'चीन के एक प्रांत' के रूप में माना जाए और वहां यह दौड़ चीनी झंडे के नीचे हो।

एक ओर तो चीन सरकार इन प्रदर्शनों की यह कहकर निंदा कर रही थी कि ये संगठन खेल का राजनीतिकरण करके ओलंपिक की भावना का अपमान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर खुद चीन सरकार हर चरण पर ओलंपिक का इस्तेमाल अपने ऐसे राजनीति लक्ष्यों को पूरा करने में लगी हुई है जो सीधे–सीधे उसके उपनिवेशवादी और कम्युनिस्ट तानाशाही वाले हितों से जुड़े हुए हैं। पहले तो बीजिंग के नेताओं ने मशाल को ताइवान में चीनी झंडे तले निकालने की जिद करके अपने एक ऐसे राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति की कोशिश की जिसके लिए वह ताइवान पर सैनिक हमला करने की चेतावनियां बरसों से जारी करता आ रहा है। उसने अपने उपनिवेश सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) में मशाल के जुलूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर वहां सेना और पुलिस बलों को तैनात किया। वहां की राजधानी उरुमची में मशाल जुलूस के दिन कर्फ्यू लगाकर वहां के आम नागरिकों को घरों में बंद कर दिया और विदेशी पत्रकारों को भी समारोह स्थल से परे जाने या आम लोगों से सीधे बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी। एक उपनिवेशी कब्जे वाले इलाके में इस तरह फौजी ताकत से ओलंपिक मशाल का जुलूस निकालना यकीनन एक राजनीति कदम था जिसका असली लक्ष्य दुनिया को यह दिखाना था कि सिंकियांग चीन का ही हिस्सा है। इस तरह के ओछे राजनीतिक कदम को किसी भी मायने में ओलंपिक की खेल भावना के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

चीन सरकार ने इससे भी घटिया खेल तिब्बत में खेला। वहां भी उसका पूरा फोकस ओलंपिक भावना प्रदर्शित करने के बजाए दुनिया के सामने यह सिद्ध करने पर रहा कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है और उसपर उपनिवेशवादी कब्जे के आरोप बेबुनियाद हैं। पहले तो उसने ओलंपिक मशाल को एवरेस्ट तक ले जाने का नाटक किया। इसके लिए वहां के पर्यावरण की बर्बादी की चिंता किए बिना वहां पक्की सड़क भी बना डाली ताकि मशाल का जुलूस वहां तक जा सके। संयोग से मार्च और अप्रैल में तिब्बत में चीनी कब्जे के खिलाफ जनउभार ने पूरी दुनिया का ध्यान तिब्बत की ओर खींच लिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सेना ने दो सौ से ज्यादा तिब्बती प्रदर्शनकारियों को गोली से उड़ा दिया। उसके बाद ल्हासा शहर में ओलंपिक मशाल का जुलूस निकालने के लिए उसने वही हथकंडे अपनाए जो उसने सिंकियांग में अपनाए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने पर विचार हो रहा था तब दुनिया भर के मानवाधिकारवादी और लोकतंत्र समर्थक संगठनों ने आपत्ति दर्ज की थी कि मानवाधिकारों को कुचलने के लिए बदनाम किसी सरकार को इस तरह का सम्मान नहीं दिया जा सकता। तब ओलंपिक समिति ने यह कहकर चीन के पक्ष में फैसला लिया था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से चीन सरकार को अपनी व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने और अपने यहां मानवाधिकारों की हालत सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन वहां मानवाधिकारों की हालत में सुधार के बजाए लगातार गिरावट ही आई है। ऐसे में दुनिया भर में मानव अधिकारों, मानवीय आजादी और लोकतंत्र के समर्थक लोग और संगठन अगर ओलंपिक मशाल को माध्यम बनाकर चीन का विरोध करते हैं तो इसे एक तार्किक और वाजिब प्रतिक्रिया माना जाना चाहिए। जहां तक चीन की गुलामी में रह रहे तिब्बत, सिंकियांग और भीतरी मंगोलिया जैसे देशों की बात है, बीजिंग ओलंपिक का एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इन देशों की हालत की ओर केंद्रित हुआ है। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है। अभी तो शुरुआत है। आने वाले वर्षों में इन देशों के मुक्ति आंदोलनों को नया बल मिलेगा।

– विजय क्रान्ति

बीजिंग ओलंपिक कवरेज के लिए 20,00 पत्रकारों की फौज से चीन परेशान

पाबंदियों की लंबी सूची ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और चीन सरकार के बीच तनाव पैदा किया

पिछले दिनों सिचुआन प्रांत के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी मीडिया को अपेक्षाकृत बेरोकटोक जाने दिया गया। लेकिन मार्च में तिब्बत में फैली अशांति के दौरान वहां रिपोर्टिंग करने गए 40 से अधिक पत्रकारों को बैरंग भेज दिया गया। यही नहीं, कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गार्डियन के जोनाथन वाट्स ने अपनी निराशाभरी यात्रा का एक वीडियो तैयार किया जिसे उन्होंने शीर्षक दिया ''सेवन डेज नॉट इन तिब्बत''।

चीन सरकार ने बीजिंग के लिए ओलंपिक–2008 का दावा पेश करते हुए स्पष्ट रूप से गारंटी दी थी कि, ''ओलंपिक खेलों के मीडिया कवरेज और आयोजन स्थल के इर्दगिर्द पत्रकारों के चलने–फिरने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।'' लेकिन जिस देश का अपने ही मीडिया पर कड़ा नियंत्रण हो और जिसने अपने बाजार में विदेशी मीडिया के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाई हुई हो उसकी इस गारंटी पर शुरू से ही जबर्दस्त विवाद रहा है।

अगले कुछ सप्ताह बाद जब दुनिया भर के देशों से 20,000 पत्रकार और ब्रॉडकास्टर चीन सरकार की इस गारंटी को परखने के लिए चीन की राजधानी में उतरेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने जब 2001 में घोषणा की कि 2008 के खेलों के आयोजन का गौरव बीजिंग को दिया जा रहा है, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक और 1980 के बहिष्कृत मॉस्को ओलंपिक के बाद बीजिंग ओलंपिक संभवतया राजनैतिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील साबित होगा।

टाइम्स के ओलंपिक संवाददाता ऐशलिंग ओ' कोनोर का मानना है कि इससे रिपोर्टिंग की शक्ल बदल जाएगी। उन्होंने कहा, ''आमतौर पर एक बार खेलों के शुरू हो जाने पर उनका कवरेज खेल पृष्ठों पर सीमित हो जाता है। लेकिन इस बार, चीनी अधिकारियों ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं, इसलिए ये खेल राजनैतिक खबरों और विदेशी पृष्ठों पर भी अपनी जगह बनाने जा रहे हैं।''

पत्रकारों की सुरक्षा की पैरवी करने वाले संगठन रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक, चीन पत्रकारों को जेल में डालने वाला दुनिया का सबसे बदनाम देश है। इस साल के शुरू में वहां कम से कम 30 पत्रकार जेलों में बंद थे। इसलिए खेल और समाचार संपादकों के पास लगातार मानवाधिकार संगठनों के ईमेल आ रहे हैं। इन खेलों की अति विवादास्पद प्रकृति और मीडिया की आजादी से संबंधित चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए क्या वहां आजादी से रिपोर्टिंग करना संभव होगा?

चैनल–4 न्यूज के बीजिंग संवाददाता लिंडसे हिल्सम के मुताबिक, असल परीक्षा उस समय होगी जब खेल शुरू होंगे। वे पूछते हैं, ''क्या इंटरनेट को सचमुच सेंसर नहीं किया जाएगा? क्या पत्रकारों को घूमने–फिरने की आजादी होगी? क्या सीएनएन और बीबीसी वर्ल्ड को अब ब्लैक आउट नहीं किया जाएगा?''

जनवरी 2007 में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मान्यता प्राप्त पत्रकार चीन में तिब्बत और मुस्लिम सिंकियांग क्षेत्रों में बिना सरकारी अनुमति के घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन व्यवहार में ऐसा आंशिक रूप से ही हुआ है। पिछले दिनों सिचुआन प्रांत के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी मीडिया को अपेक्षाकृत बेरोकटोक जाने दिया गया। लेकिन मार्च में तिब्बत में फैली अशांति के दौरान वहां रिपोर्टिंग करने गए 40 से अधिक पत्रकारों को बैरंग भेज दिया गया। यही नहीं, कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गार्डियन के जोनाथन वाट्स ने अपनी निराशाभरी यात्रा का एक वीडियो तैयार किया जिसे उन्होंने शीर्षक दिया ''सेवन डेज नॉट इन तिब्बत''।

दरअसल, तिब्बत और सिचुआन के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तिब्बती विरोध राजनीतिक थे जबकि भूकंप गैरराजनैतिक था। बीबीसी के वर्ल्ड न्यूज एडीटर जॉन विलियम्स चीनी सरकार के रवैए के बारे में बताते हैं, जब उनका बर्ताव अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है और जब बुरा होता है तो भयानक होता है।'' चीन में इंटरनेट तक पहुंच हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। वहां चीन सरकार तय करती है कि आप क्या देख सकते हैं और कया नहीं। बीबीसी न्यूज साइट के बारे में चुनौती देने पर चीनी सरकार हमेशा इस बात से इनकार करती है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। वह इस साइट के न खुलने की वजह 'तकनीकी गड़बड़ी' बताती है। इस साल मार्च में तिब्बती प्रदर्शनों के दौरान, चीन में गार्डियन की साइट को पहली बार थोड़े समय के लिए ब्लॉक किया गया था।

फिर मार्च के अंत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के दौरे से ठीक पहले अंग्रेजी में बीबीसी न्यूज साइट को अचानक और बिना किसी स्पष्टीकरण के खोल दिया गया।। ऐसा 10 वर्षों में पहली बार हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बीबीसी की चीनी भाषा साइट को अभी तक ब्लॉक किया हुआ है। यह स्थिति वर्ल्ड सर्विस के रेडियो प्रसारण की भी है। जहां चीनी प्रसारणों को जाम कर दिया गया है, वहीं अंग्रेजी कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं है। अपने सबसे हाल के बीजिंग दौरे के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने कहा, ''इंटरनेट सहित कई क्षेत्रों में आश्वासन से

संतुष्ट हैं।'' लेकिन एक महीने बाद चीन के प्रौद्योगिकी मंत्री वान गांग ने कहा, ''मुझे इस बारे में कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं मिली है कि कौन सी साइटें दिखाई जाएंगी और कौन सी बंद रहेंगी...हर देश में कुछ वेबसाइटों पर प्रतिबंध होता है।'' हिल्सम के अनुसार, इंटरनेट तक कभी पहुंच होती है और कभी नहीं।

विकीपीडिया कभी–कभी गायब हो जाता है और ह्यूमन राइट्स वाच तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल सरीखे साइट अभी भी ब्लॉक हैं। उन्होंने कहा, ''यदि तीन हफ्ते तक चलने वाले ओलंपिक के दौरान सभी अंग्रेजी साइटें खोल दी जाती हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उसके बाद क्या होगा।''

ओलंपिक खेलों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण खिड़की टेलीविजन होगा। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें ही खेल के स्वरूप को तय करेंगी। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में चार अरब लोग टेलीविजन पर ओलंपिक खेल देखेंगे। डेव गोर्डन, जो बीबीसी के ओलंपिक कवरेज के प्रभारी हैं, कहते हैं, ''यह मेरे लिए खबरों के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमने ओलंपिंक के उद्घाटन समारोह को किसी सामान्य खेल आयोजन जैसा पेश न करने का निर्णय किया है। इसके कवरेज में हुव एडवर्ड्स के समाचार, हाजेल इर्विन की खेल खबरें और बीजिंग में संवाददाता रहीं कैरी ग्रेसी के विश्लेषण होंगे।

समारोह और खेल स्पर्धाओं की तस्वीरें एक विशिष्ट पूल फीड से मिलेंगी। ये तस्वीरें ओलंपिक का मेजबान ब्रॉडकास्टर बीजिंग ओलंपिक ब्रॉडकास्टिंग मुहैया कराएगा। यह एक संयुक्त चीनी–विदेशी कंपनी है जिसे इन खेलों के लिए खासतौर पर स्थापित किया गया है। हर प्रसारण अधिकार धारक के लिए हर आयोजन स्थल से हर स्पर्धा की एक जैसी तस्वीरों का एक सेट उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर कोई 3,800 घंटे के लाइव फीड्स होंगे। किसी भी समय कोई भी ब्रॉडकास्टर 20 फीड्स तक ले सकता है। चूंकि चीनियों का यह रिकॉर्ड रहा है कि उन्हें जो टेलीविजन कवरेज पसंद नहीं होता उसे वे सेंसर कर देते हैं, इसलिए ओलंपिक की संभावित सेंसरशिप गर्म मुद्दा बन गया है।

बताया जाता है कि एक बार चीनी अधिकारियों ने लाइव फीड्स विलंब से देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन गोर्डन कहते हैं, ''हमें पूरा आश्वासन दिया गया है फीड्स लाइव होंगे।'' लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किसी प्रदर्शन के कवरेज में मेजबान ब्रॉडकास्टर की क्या नीति होगी। गोर्डन कहते हैं, ''हम उम्मीद करते हैं कि स्टेडियम के भीतर मैदान में और उसके बाहर जो कुछ होगा, उसे पूरी तरह कवर किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई संपादकीय नीति थोपी जाए। लेकिन अगर स्थिति पैदा होती है तो कुछ स्पर्धाओं के दौरान बीबीसी के खुद के कैमरे होंगे जिनका इस्तेमाल उन क्षणों को कैद करने के लिए किया जाएगा जिनकी हमें जरूरत महसूस होगी।''

फ्रांसीसी टेलीविजन ने कहा है कि यदि तस्वीरों पर किसी भी तरह की सेंसरशिप लगाई गई तो वे कवरेज का बहिष्कार करेंगे। ओलंपिक के दौरान चीन के घरेलू दर्शक क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं? जब पूरी दुनिया में चीनी भूकंप के निरंतर कवरेज ने दूसरी सभी खबरों को हाशिए पर नहीं धकेल दिया था तब भी चीन के सरकारी सीसीटीवी पर ओलंपिक से संबंधित आत्मप्रशंसा वाली खबरें निर्जज्जता से दिखाई जा रही थीं। चीन में मशाल जुलूस के हर चरण की रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्य खबर के रूप में दिखाई जा रही थी। जिस दिन मकाओ में मशाल जुलूस का ड्रेस रिहर्सल हुआ केवल उसी दिन इसे खबरों में दूसरा स्थान दिया गया। शुरू के विरोध प्रदर्शनों के विदेशी कवरेज में चीन ने काफी चौकसी बरती थी। पश्चिमी मीडिया ने जिस मुस्तैदी से विरोध प्रदर्शनों और मानवाधिकारों के हनन की खबरें दी थीं, उससे चीनी मीडिया बेहद आहत और नाराज था। बीबीसी और सीएनएन दोनों को अपने कवरेज के लिए भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब तो ऐंटी–सीएनएन.कॉम नाम से एक चीनी वेबसाइट भी शुरू हो गई है।

बहरहाल, खेलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए यह तनावपूर्ण समय होगा। यदि ओलंपिक को सफल आयोजन के रूप में चित्रित किया जाएगा तो मीडिया पर चीनी प्रोपेगेंडा का शिकार होने का आरोप लगेगा। दूसरी तरफ यदि वहां विरोध प्रदर्शन होते हैं और मीडिया उनकी समुचित रिपोर्टिंग करता है तो चीनी सरकार आरोप लगाएगी कि गैर प्रतिनिधि अलपसंख्यक समुदाय की कार्रवाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जॉन विलियम्स पत्रकारों को चेतावनी देते हैं कि वे पूर्वाग्रहों के साथ चीन न जाएं। वे कहते हैं, ''अगर हम तिब्बत और विरोध प्रदर्शनों का चश्मा लगाकर खेलों को कवर करेंगे तो यह हमारे लिए गलत होगा। लेकिन हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।''

ब्रिटिश समाचार पत्र ***गार्डियन*** से साभार

फ्रांसीसी टेलीविजन ने कहा है कि यदि तस्वीरों पर सेंसरशिप लगाई गई तो वे कवरेज का बहिष्कार करेंगे। जब चीनी भूकंप ने दुनिया में दूसरी सभी खबरों को हाशिए पर धकेल दिया था तब भी चीनी टीवी ओलंपिक से संबंधित आत्मप्रशंसा वाली खबरें निर्जज्जता से दिखा रहा था। ओलंपिक मशाल की रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी और सीएनएन को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब तो ऐंटी–सीएनएन.कॉम नाम से एक चीनी वेबसाइट भी शुरू हो गई है।

अधिवेशन में मुख्य अतिथि श्री यशवंत सिन्हा : भारत के स्वाभिमान को आहवान

तिब्बत की आजादी के आंदोलन में भारतीय जनता की भूमिका महत्वपूर्ण

चंडीगढ़ में भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों के अधिवेशन में आंदोलन को नई गति देने का फैसला

तिब्बती प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने कहा कि तिब्बत में 10 मार्च से चल रहा आंदोलन वहां वर्षों से व्याप्त असंतोष का परिणाम है। चीन भले ही कितना ताकतवर हो पर सत्य और अहिंसा के इस आंदोलन के सामने वह बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा।

भारत में तिब्बत समर्थक समूहों का विशेष सम्मेलन 28–29 जून को चंडीगढ़ के बाबा मक्खन शाह लुबाना आडिटोरियम में हुआ जिसमें देश भर के लगभग 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें तिब्बत की स्थिति पर विचार के अलावा आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गयी। सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर तिब्बती प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने कहा कि तिब्बत में 10 मार्च से चल रहा आंदोलन वहां वर्षों से व्याप्त असंतोष का परिणाम है। चीन भले ही कितना ताकतवर हो पर सत्य और अहिंसा के इस आंदोलन के सामने वह बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा।

अधिवेशन का आयोजन भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों के केंद्रीय समन्वय संगठन कोर ग्रुप फॉर तिबेतन कॉज़ ने किया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव के कारण आज तक तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा बना हुआ है।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोशियारी ने कहा कि पचास साल पहले तिब्बत पर चीन के कब्जे के समय भारत द्वारा चुप रहना बहुत बड़ी भूल थी।

भारत–तिब्बत संसदीय मंच के संयोजक श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि तिब्बत के सवाल पर चीन अलग–थलग पड़ने लगा है। बीजिंग ओलंपिक के बहाने दुनिया का ध्यान तिब्बत की ओर जा रहा है।

समाजवादी नेता सांसद ब्रजभूषण तिवारी ने भारत के तिब्बत आंदोलन में डा. राममनोहर लोहिया की भूमिका को याद करते हुए कहा कि आज भी ऐसे ही एक नेता की जरूरत तिब्बती आंदोलन को है।

प्रो. आनंद कुमार ने भारतीय संसद से अपील की कि वह तिब्बत समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए। श्री कुलदीप अग्निहोत्री का कहना था तिब्बत की आजादी भारत के भी उतने ही हित में है जितनी तिब्बती जनता के हित में है।

हिमाचल सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री राजीव बिंदल ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि दुनिया भर के देश तिब्बत पर हो रहे अन्याय के प्रति उदासीन बने हुए हैं। गांधीवादी श्री रामजी बाबू ने विश्वास व्यक्त किया कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर तिब्बत को आजादी मिलना एकदम निश्चित है।

अधिवेशन में तिब्बत आंदोलन के बारे में एक घोषणा स्वीकार की गई और कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए जो इस प्रकार हैं:

चंडीगढ़ घोषणा

यह सम्मेलन उन सभी तिब्बतियों को सलाम करते हैं जिन्होंने 10 मार्च 2008 से शुरू हुए जन आंदोलन के माध्यम से चीनी दमन और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाया है। पिछले कुछ महीनों से हम तिब्बती आम नागरिकों, छात्रों और भिक्षु–भिक्षुणियों द्वारा किए जा रहे त्याग से बहुत प्रभावित हैं।

यह विशेष सम्मेलन चीनी अधिकारियों द्वारा दो सौ से तिब्बतियों के मारे जाने तथा पांच हजार से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को जेलों में बंद किए जाने से बहुत व्यथित है। बड़े दुख की बात है कि चीन अधिकारियों ने अपनी गलत नीति और कार्यवाही के लिए परमपावन दलाई लामा चीनी आधिपत्य में तिब्बती सभ्यता को लोप होने से बचाने के लिए मध्यमार्ग के प्रवक्ता हैं।

भारत के अनेक भागों से आए तिब्बत के समर्थक समूहों के प्रतिनिधि तिब्बत मुक्ति साधना का पूर्ण समर्थन करते हैं क्योंकि तिब्बत को बचाने के लिए हिमालय क्षेत्र को सुरक्षित करने तथा एशिया में शांति स्थापित करने का यही एक मार्ग है। न्याय और गरिमा की तलाश में तिब्बत विश्व में अकेला नहीं है बल्कि चीन पर तिब्बती मामले की अनदेखी न करने के लिए

विश्व जनमत का भारी दबाव है।

हम उन सभी व्यक्तियों, संगठनों और देशों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने तिब्बत पर अवैध चीनी कब्जे का विरोध ओलंपिक मशाल की विश्वव्यापी यात्रा के दौरान किया। प्रतिनिधियों को ऐसे खिलाड़ियों, कलाकारों और राजनीतिक व्यक्तियों पर गर्व है जिन्होंने भारत में ओलंपिक मशाल के आगमन पर उपस्थि रहने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। हमें आशा है कि भारत सहित विश्व के अनेक खिलाड़ियों का समर्थन तिब्बत और तिब्बत की जनता को मिलेगा। यदि चीन दलाई लामा जी के साथ अर्थपूर्ण वर्ता नहीं प्रारंभ करता है तो 8 से 24 अगस्त को होने वाले बीजिंग ओलंपिक खेलों को तिब्बत में चल रहे दमन और अत्याचार के कारण शर्म के खेल के रूप में याद किया जाएगा।

चंडीगढ़ में चल रहा भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों का यह सम्मेलन मांग करता है कि:

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद मानवाधिकार आयोग की आपात बैठक बुलाए तथा विशेष जांच दल को तिब्बत की स्थिति के अध्ययन के लिए मठों तथा जेलों की यात्रा पर भेजे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा में तिब्बत के मामले पर बहस हो तथा चीन और परमपावन दलाई लामा के बीच प्रभावकारी और अर्थपूर्ण वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया जाए।
2. चीन सरकार पंचेन लामा समेत सभी तिब्बती राजनीतिक बंदियेां को रिहा करे तााि तिब्बत में संस्कृतिक नरसंहार रोकने के लिए विश्व जनमत द्वारा किए गए निवेदन पर तुरंत ध्यान दे।
3. भारत की सरकार परमपावन दलाई लामा और चीन के बीच वार्ता प्रारंभ कराने के लिए रचनात्मक पहल करे क्योंकि तिब्बत के स्वराज्य के बिना हिमालय क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती है।
4. भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों का चंडीगढ़ सम्मेलन घोषणा करता है कि तिब्बत के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता दिन प्रतिदिन गहराएगी और चीनी दमनचक्र चलने के बावजूद मजबूत होती रहेगी। हम जानते हैं कि दुनिया की कोई भी शक्ति मानव आत्मा को किसी भी तरह से दबा नहीं सकती क्योंकि सत्य, करूणा और त्याग के साथ असत्य और अन्याय के संघर्ष में हमेशा विजयी होता है।
5. हम लोगों की विश्वास है कि तिब्बत की जनता परमपावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में विश्व के विभिन्न देशों का अत्याधिक समर्थन प्राप्त करेगी। वे बुद्ध के ज्ञान, सत्य और न्याय में निष्ठा के प्रतीक हैं। हम सभी तिब्बत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए कायक्रमों के माध्यम से विश्व जनमत बनाने के लिए भारत और दुनिया भर के देशों में योगदान करने का आहवान करते हैं।

अधिवेशन में स्वीकृत कार्ययोजना

अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया कि आगामी 12 महीने का समय तिब्बत मुक्ति साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। इसलिए कोर ग्रुप ने जिन कार्यक्रमों के लिए सहमति बनायी है वे इस प्रकार हैं :.

1. 6 जुलाई – परमपावन दलाई लामा जी के जन्मदिवस पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएं और तिब्बत मुक्ति साधना की सफलता के लिए कामना की जाए।

2. 21 जुलाई – परमपावन दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत शुरू कराने में भारत सरकार को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए संसद से पंचायत तक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच महीने भर का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए।

3. 8 अगस्त – तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के विरोध में बीजिंग ओलंपिक आरंभ होने के दिन 8 अगस्त को भारत भर में 'काला दिवस' के रूप में मनाया जाए।

4. 16 अगस्त – रक्षाबंधन के दिन तिब्बती महिलाएं प्रमुख भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के हाथ में राखी बांधने के कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

5. 24 अगस्त – इस दिन बीजिंग में ओलंपिक खेल समाप्त होंगे। इस दिन भारत भर में प्रदर्शन आयोजित करके तिब्बत और चीन में हो रहे मानवाधिकार हनन का विरोध किया जाएगा।

6. जुलाई–अगस्त – तिब्बत की फ्रीडम–टार्च का देश भर में स्वागत किया जाए।

7. सितंबर–अक्तूबर – अरुणांचल तथा दूसरे सीमावर्ती स्थानों पर चीन के सैनिक अतिक्रमण के बारे में जनजागरण के लिए तावांग से भारत–तिब्बत सीमा यात्रा समेत भारत भर में यात्राएं निकाली जाएं।

8. सितंबर–दिसंबर – कोर ग्रुप के उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, और दक्षिणी क्षेत्रों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

इनके अलावा भारत के अभाविप और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों के साथ साझा कार्यक्रमों के आयोजन, विश्वविद्यालयों में निबंध, चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन, पूर्व सैनिकों के सैल का गठन, प्रचार अभियान और 10 दिसंबर के दिन बड़े पैमाने पर मानवाधिकार दिवस के आयोजन पर भी सहमति हुई।

हम उन सभी व्यक्तियों, संगठनों और देशों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने तिब्बत पर अवैध चीनी कब्जे का विरोध ओलंपिक मशाल की विश्वव्यापी यात्रा के दौरान किया। प्रतिनिधियों को ऐसे खिलाड़ियों, कलाकारों और राजनीतिक व्यक्तियों पर गर्व है जिन्होंने भारत में ओलंपिक मशाल के आगमन पर उपस्थि रहने का निमंत्रण ठुकरा दिया था।

चीन के साइबर आतंकवाद ने दुनिया भर में परेशानी पैदा की

भारत के सुरक्षा नेटवर्क सिस्टम में चीन की घुसपैठ से भारत सरकार चिंतित

श्रीराम चौलिया, एशिया सेंटिनल से साभार

इस कार्रवाई को एक राष्ट्रीय संस्थान पर आतंकवादी हमले के समान माना जा रहा है जिससे भारत के कूटनीतिक और सैन्य संचार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हालांकि दिल्ली में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने इस घटना के समाचार को मनगढ़ंत बताया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन योजनाबद्ध तरीके से सरकारी वेबसाइटों पर हमला करता है और बाद में उसकी खबरें छपने पर उसका खंडन करता है।

चीन आजकल एक नई गतिविधि में शामिल हो गया है। वह दुनिया भर के सरकारी कंप्यूटरों में चोरी–चुपके झांक रहा है जो गैरकानूनी और अनुचित है। भारत भी उसकी इस गतिविधि से अछूता नहीं है। पिछले साल तो अमेरिकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स के ईमेल सिस्टम में चीनियों का अतिक्रमण विश्व मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। दरअसल चीनी हैकर दुनिया के तमाम देशों की कंप्यूटर प्रणालियों में घुस रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण भारत के विदेश मंत्रालय के वेब सर्वर में उनका घुसना है।

इस कार्रवाई को एक राष्ट्रीय संस्थान पर आतंकवादी हमले के समान माना जा रहा है जिससे भारत के कूटनीतिक और सैन्य संचार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हालांकि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए इस घटना के समाचार को मनगढ़ंत बताया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन योजनाबद्ध तरीके से सरकारी वेबसाइटों पर हमला करता है और बाद में उसकी खबरें छपने पर उसका खंडन करता है।

मिसाल के तौर पर मई 2007 में एक खबर आई कि चीनियों ने जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल के कार्यालय और उनके तीन मंत्रियों के कंप्यूटर सिस्टम पर धावा बोल दिया है। फिर जून में खबर आई कि वे गेट्स के ईमेल सिस्टम में घुस गए हैं। सितंबर में ब्रिटिश सरकार ने रहस्योद्घाटन किया कि एक हैकिंग यूनिट, जिसकी जड़ें चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में पाई गईं, ने विदेश कार्यालय और लंदन स्थित अन्य विभागों के नेटवर्क पर हमला बोल दिया।

हालांकि बीजिंग ने हर आरोप को 'दुर्भावनापूर्ण प्रचार' बताते हुए उस पर जबर्दस्त आपत्ति की, लेकिन इन ऑपरेशनों में चुराए गए डाटा की प्रकृति को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह सब चीन सरकार की जानकारी में हुआ। तर्क दिया जा रहा है कि हैकर, जिनके आइपी पते चीन की मुख्यभूमि के हैं, शरारती व्यक्ति हैं जो अपनी विध्वंसक तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते हैं अगर ऐसा है तो चीन ने अभी तक किसी हैकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? दरअसल, कानूनी कार्रवाई के अभाव में ही इस तरह के हैकरों की संख्या बढ़ती जा रही है।

यह विडंबना ही है कि एक कथित कम्युनिस्ट देश में, जहां श्रमजीवी वर्ग को संगठित करने पर प्रतिबंध है, हैकरों की 'यूनियनें' और 'लाल गठजोड़' हैं जिनमें शामिल चीनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर 'देशभक्ति' के तथाकथित काम करने के लिए तैयार रहते हैं। सन् 1998 से 2002 तक 'रेड हैकर' अमेरिका, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान के हजारों वेबसाइटों में घुस गए और कंप्यूटर सिस्टम को पंगु कर दिया।

चीन की मुख्यभूमि में स्थित हांकर यूनियन उस समय राष्ट्रीय संपत्ति बन गई जब 2001 में जासूसी विमानों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव पैदा हो गया। उसके सदस्यों ने अमेरिका की कई सरकारी वेबसाइटों को बर्बाद कर दिया। अमेरिकी हैकरों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया।

उस बहुचर्चित साइबर युद्ध के बाद हांकर यूनियन ने 2003 में जापान के खिलाफ ऑनलाइन हमलों और याचिकाओं का अंबार लगा दिया। सन् 2005 में हैकिंग दस्तों ने जापान में दर्जनों सरकारी और निजी वेबसाइटों पर हमला बोल दिया। वाशिंग्टन पोस्ट ने इसे किसी राष्ट्र के कंप्यूटर सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। लेकिन चीन के लोगों ने हांकर यूनियन के सदस्यों का गुणगान करते हुए चर्चित हैकरों का अभिनंदन किया। इन हांकरों ने भी मीडिया को अपने कारनामों के बारे में बढ़चढ़ कर बताया।

साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाए चीनी समाज और राज्य ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बताया। उल्लेखनीय है कि साइबर अपराधियों को गिरफ्तार न करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक नियमों के खिलाफ है। चीनी जनसंपर्क विशेषज्ञ सु वु के अनुसार मातृभूमि के हित में हैकिंग करना ''चीन के एक सदी पुराने राष्ट्रवादी आंदोलन का विस्तार है।'' राज्य संचालित शोध संस्थान और मीडिया घराने भी उनका गुणगान कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस माओवादी सिद्धांत पर चल रहे हैं कि ''यदि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा।'' जाहिर है इस तरह के माकूल माहौल में हैकिंग फूलता–फलता उद्योग बन गया है।

चीन में जहां इंटरनेट सर्च इंजन और राजनैतिक रूप से आपत्तिजनक वेबसाइटों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, वहीं हैकरों को खुली छूट मिली हुई है। निरंकुश चीन को ऐसी टेक्नोलॉजी से भय लगता है जिनके जरिए उसके नागरिक लोकतंत्र, मानवाधिकारों, धार्मिक आजादी और तिब्बत तथा सिंकियांग सरीखे

आत्मनिर्णय के संघर्षों से संबंधित क्रांतिकारी सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं। सन् 2004 में चीनी सरकार और गूगल के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत गूगल ने अपने सर्च नतीजों में चीन से संबंधित विवादास्पद खबरें देना बंद कर दिया।

मार्च में जब तिब्बती असंतोष फैला तो चीन ने उससे संबंधित खबरें बाहर न जाने के लिए तुरंत गूगल न्यूज और यूट्यूब एक हफ्ते के लिए लॉक कर दिया। दरअसल तिब्बत या फालुन गोंग आध्यात्मिक आंदोलन से संबंधित मुद्दों पर चीनी सरकार की इंटरनेट सेंसरशिप उस लंबी रस्सी का हिस्सा है जो जापान विरोधी दंगे भड़काने या लक्षित देशों से गोपनीय जानकारी चुराने के लिए हैकरों को थमायी गयी है। इस विरोधाभासी स्थिति से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नई टैक्नोलॉजी चीनी शासन के लिए दोधारी तलवार है।

यदि इंटरनेट चीन का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे खराब दुश्मन बन सकता है तो कुशलता से उसके प्रबंधन की जरूरत है। लेकिन चीन की नीति अपने सैन्य आधुनिकीकरण अभियान के अंग के रूप में अपनी साइबर युद्ध क्षमता को विकसित करना है। साथ ही ऐसी वेबसाइटों पर कड़ी नजर रखना है जो लोगों के बीच असंतोष और अशांति फैला सकती हैं।

कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट की प्रकृति के कारण साइबर अपराधों को कारगर तरीके से रोकना मुश्किल है। अगर साइबरस्पेस को नियंत्रित करने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हो भी जाए तो चीन से नियमों के पालन की उम्मीद करना बेकार है।

भारत सरीखे शिकार देशों के पास एकमात्र विकल्प यह है कि वे चीनी हैकिंग की हर घटना का अपने घर में प्रचार करें और इस आक्रामक बर्ताव की तरफ अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करें। दुनिया के सामने चीन की हैकिंग रणनीति का जितना पर्दाफाश होगा, इंटरनेट नेटवर्क सुरक्षा में सुधार की उतनी जरूरत महसूस होगी। साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भारत का वैश्विक नेतृत्व चीनी हैकरों की घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा के ठोस उपाय विकसित कर सकता है। जहां तक पलटवार की बात है तो भारतीय हैकर अतीत में पाकिस्तानी वेबसाइटों के खिलाफ मिनी–साइबर युद्ध लड़ चुके हैं। लेकिन चीन की कड़ी चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से संगठित होने की जरूरत होगी।

श्रीराम चौलिया साइराक्यूज, न्यूयॉर्क के मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप में अंतरराष्ट्रीय मामलो के शोध कर्ता हैं।

चीन को डर है कि बुरे प्रचार से ओलंपिक में कम दर्शक आ सकते हैं

सरकार की सुरक्षा नीति ने दर्शकों को डराया

बीजिंग एक वरिष्ठ चीनी पर्यटन अधिकारी ने स्वीकार किया है कि ओलंपिक से पहले दुनिया भर में चीन के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार के कारण कम संख्या में विदेशी खेल प्रेमी बीजिंग आ सकते हैं।

इस साल के शुरू से ही दक्षिणी चीन में बर्फीले मौसम के कारण लाखों लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तिब्बत में अशांति फैली हुई है, ओलंपिक मशाल जुलूस के अंतरराष्ट्रीय चरण में चीन विरोधी प्रदर्शन हुए हैं और अब भूकंप से सिचुआन तबाह हो गया है। चीनी सरकार दावा कर रही है कि उसने ओलंपिक पर सिंकियांग के स्थानीय उइगुरों के हमले की साजिश का पता लगाकर उसे कुचल दिया है।

बीजिंग पर्यटन प्रशासन की निदेशक झांग हुइगुआंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''भूकंप या किसी दूसरी चीज का असर हो या न हो, लेकिन मेरा मानना है कि चीन की स्थिति को न समझने वाले कुछ विदेशी पर्यटकों पर मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है।''

उम्मीद की जा रही है कि बीजिंग अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान 450,000 से 500,000 विदेशी पर्यटकों की मेजबानी करेगा। बीजिंग ओलंपिक का उद्घाटन समारोह महज एक महीने दूर है, लेकिन होटलों में बुकिंग बहुत कम हुई है। चार सितारा होटलों का कहना है कि ओलंपिक खेलों के लिए उनके महज 44 प्रतिशत कमरे बुक हुए हैं। झांग ने कहा, ''कछ ट्रैवल एजेंटों को अभी तक ओलंपिक टिकट नहीं मिले हैं जिससे कुछ टूर ग्रुपों को समस्या हो रही है। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वे संभवतः नहीं आएंगे क्योंकि टिकट के बिना आने का कोई लाभ नहीं होगा।''

हालांकि चीन संदेश दे रहा है कि वह ओलंपिक खेलों में सभी का स्वागत करेगा, लेकिन सरकार वीजा देने में काफी कड़ाई बरत रही है। उसका कहना है कि ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। झांग ने नई व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग खेल देखने आना चाहते हैं, वे अभी भी वीसा ले सकते हैं। बहरहाल, बीजिंग की खुद की टूरिज्म पब्लिसिटी विदेशियों को चेतावनी दे रही है कि चीनी अधिकारी तंत्र से निपटना मुश्किल हो सकता है।

चार सितारा होटलों का कहना है कि ओलंपिक खेलों के लिए उनके महज 44 प्रतिशत कमरे बुक हुए हैं। झांग ने कहा, ''कछ ट्रैवल एजेंटों को अभी तक ओलंपिक टिकट नहीं मिले हैं जिससे कुछ टुअर ग्रुपों को समस्या हो रही है। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वे संभवतः नहीं आएंगे क्योंकि कमरों और कारों का किराया मंहगा हो जाएगा।''

कैमरे की अ

1. भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों का विशेष अधिवेशन कोर ग्रुप फॉर तिबेतन
2. 17 जुलाई को परमपावन दलाई लामा की फिलाडेल्फिया यात्रा के दौरान वहां
3. बीजिंग ओलंपिक मशाल को दुनिया भर में मिले विरोध के बाद चीन सरकार
4. ल्हासा में ओलंपिक मशाल पहुंचने पर पूरे शहर को फौजी छावनी जैसा रूप
5. 26 जून के दिन परमपावन कर्मा पा ने धर्मशाला के ग्यूतो विश्वविद्यालय मठ
6. यूरोपीय संसद की मानवाधिकार कमेटी के सामने तिब्बती प्रतिनिधियों सुश्री के
7. जंतर मंतर पर तिब्बत सोलिडेरिटी कमेटी के धरने में एकजुटता प्रदर्शित करने
8. तिब्बती युवा कांग्रेस के 6 कार्यकर्ताओं द्वारा निर्जल आमरण अनशन शुरू होने
9. 28 जुलाई को शुरू हुए इस अनशन को भारतीय तिब्बत समर्थकों से भरपूर स
10. 19 जून के दिन काठमांडू नेपाल में स्थानीय तिब्बतियों के बीजिंग–ओलंपिक

♦ आंखों देखी

की आंख से

तिबेतन कॉज़ ने 28–29 जून को चंडीगढ़ में आयोजित किया।

ौरान वहां रहने वाले तिब्बती और कलमीकिया के बच्चों ने उनका स्वागत किया।

सरकार ने ल्हासा में उसके जुलूस में तिब्बती आम जनता को शामिल नहीं होने दिया।

ैसा रूप दे दिया गया। मशाल से पहले पोताला के सामने परेड करते चीनी सैनिक।

ालय मठ में प्रवचन दिया।

ों सुश्री केलसांग ताकला और श्री जाम्पेल चोसांग ने तिब्बत का केस प्रस्तुत किया।

र्शित करने के लिए 10 जुलाई के दिन आए भारतीय सांसद श्री किरण रिजुजू।

शुरू होने के अवसर पर जंतर मंतर पर सांसद श्री बशिष्ट नारायण सिंह।

भरपूर समर्थन मिला। अनशनकारियों को स्कार्फ भेंट करते श्री सुरेंद्र कुमार सिंह।

ओलंपिक विरोधी प्रदर्शनों को नेपाली पुलिस ने इस अंदाज़ में नियंत्रित किया।

फोटो परिचय ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में

सिंकियांग के काशगर में उइगुर परिवार और चीनी सैनिक : उपनिवेशवाद का खेल

चीन ओलंपिक का इस्तेमाल सिंकियांग के उइगुरों को कुचलने के लिए कर रहा है

'आतंकवाद' के नाम पर अमेरिका का भी समर्थन

द न्यूयार्क टाइम्स से साभार

चीन सरकार का दावा है कि 1990 और 2001 के बीच उइगुर 'अलगाववादियों' के आतंकवादी हमलों में 162 लोग मारे गए। इस दौरान चीन ने इस तरह की अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 200 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

काशगर, सिंकियांग – सुदूर पश्चिमी चीन के नियंत्रण वाले इस मुस्लिम क्षेत्र से इस साल आतंकवादी साजिश की आने वाली खबरें चौंकाने वाली हैं और मनगढ़ंत भी लग सकती हैं। जरा इन खबरों पर गौर कीजिए : एक विमान में विस्फोट की साजिश को नाकाम कर दिया गया; ओलंपिक खेलों के दौरान बमबारी के लिए छिपाए गए टीएनटी बारूद का जखीरा पकड़ा गया; ओलंपिक खिलाड़ियों के अपहरण की साजिश रचने वाले 'एक हिंसक आतंकवादी गिरोह' को भी गिरफ्तार किया गया।

ये खबरें इंटरनेट पर पोस्ट अटकलें नहीं हैं बल्कि चीन सरकार की ओर से जारी की गई हैं। इसलिए मैं आतंकवादियों की खोज में विमान से काशगर गया जो प्राचीन सिल्क रोड पर नखलिस्तान जैसा है। मीनारें, ऊंट और गलीचे इसे मध्य–पूर्वी परिवेश मुहैया कराते हैं। काशगर पहुंचे हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे कि चीन के खुफिया पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो (पी एस बी) ने मुझे ढूंढ़ लिया। मेरे वीडियोग्राफर ने जो खुद एक चीनी था, फोन किया कि सादे कपड़ों में दो अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि अधिकारियों ने मुझे आपको कुछ भी न बताने की हिदायत दी है क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिकी पत्रकार इस तरह के मामलों में बहुत संवेदनशील होते हैं।

यह पूछताछ इस बात की प्रतीक थी कि चीनी अधिकारी पश्चिमी चीन में इस मुस्लिम क्षेत्र की स्थिरता को लेकर कितने चिंतित थे। यहां सिंकियांग क्षेत्र में अलगाववादियों का लक्ष्य 'पूर्व तुर्किस्तान' का निर्माण करना है। वे आए दिन यहां पर थानों को विस्फोट से उड़ाते रहते हैं। सन् 1997 में तो उन्होंने तीन सरकारी बसों को बम का निशाना बनाया था।

चीन सरकार का दावा है कि 1990 और 2001 के बीच उइगुर 'अलगाववादियों' के आतंकवादी हमलों में 162 लोग मारे गए। इस दौरान चीन ने इस तरह की अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 200 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

चीनी अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल अलकायदा के सहयोग से चल रहे एक उइगुर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर पुलिस छापे के दौरान 18 लोग मारे गए थे। वहां से 1500 हथगोले भी बरामद हुए। फिर इस साल मार्च में चीन ने ऐलान किया कि उसने सिनकियांग की राजधानी उरूम्ची से एक यात्री विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 'उसे उड़ाने की साजिश' को नाकाम कर दिया। अप्रैल में अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आत्मघाती बम हमलों की योजना बनाने वाले उइगुरों के पास विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के एक प्रवक्ता वु हेपिंग ने कहा, ''इस हिंसक आतंकवादी गिरोह ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान पत्रकारों, पर्यटकों और खिलाड़ियों के अपहरण की साजिश रची थी।''

फिर इस महीने, शंघाई में एक भीड़ भरी बस पर बम फेंका गया जिसमें तीन लोग मारे गए और कई घायल हो गए। किसी ने सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन इस घटना ने 1997 में हुई उइगुर बस बमबारी की याद जरूर ताजा कर दी। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल रोनाल्ड नोबल ने एक संवाददाता सम्मेलन में इन खबरों का हवाला दिया। उन्होंने उन खबरों का भी उल्लेख किया जिनमें कहा गया है कि ओलंपिक खेलों में व्यवधान पहुंचाने के लिए अलगाववादी जहरीली गैस से हमले की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक पर आतंकवादी हमले की पूरी संभावना है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या उद्देश्य है। जब मैं काशगर में घूमा तो मुझे स्थिति पूरी तरह शांत नजर आई। मैने यह उमीद नहीं की थी कि मैं कोई आतंकवादी सेल खोज निकालूगा, लेकिन मैने यह कल्पना जरूर की थी कि वहां का माहौल सरकार के खिलाफ होगा। मैंने जिन सामान्य उइगुरों से

बातचीत की, उन्होंने नपी–तुली शिकायतें कीं, लेकिन वे तिब्बतियों की तरह गुस्से से नहीं उबल रहे थे। एक उइगुर दुकानदार ने कहा, ''जब यहां चीनी घूमते हैं तो उन्हें कोई पसंद नहीं करता। यकीनन हम परेशान हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?''

एक युवा महिला ने दूसरी कहानी सुनाई। उसने हंसते हुए कहा, ''मैं जब छोटी बच्ची थी तो मेरी मां मुझ से कहा करती थी, ''बाहर मत घूमो, नहीं तो हान चीनी तुम्हें उठा ले जाएंगे। वे आदमी का मांस खाते हैं।'' अब हम अधिक हान चीनियों को देखते हैं लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। उनसे हमारे संबंध ठीक–ठाक हैं।''

कुछ युवा उइगुरों ने बीजिंग ओलंपिक की आलोचना की। उनका कहना था कि ओलंपिक खेलों में सारा स्थानीय बजट चला जाएगा। मैंने इससे भी अधिक सरकार विरोधी भावना शायद मैनहट्टन के किसी नुक्कड़ पर सुनी होती। काशगर में मैं जहां भी जाता, राज्य सुरक्षा अधिकारी साए की तरह मेरे पीछे लगे रहते। मेरे लिए यह बड़ा दिलचस्प नजारा था।

आमतौर पर चीनी सरकार सुरक्षा खतरों के बारे में अधिक ढोल नहीं पीटती, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि चीन उइगरों से संबंधित मामलों की आड़ में शांतिपूर्ण उइगुर असंतुष्टों का दमन करता है। अमेरिका की 9/11 घटना के बाद चीन ने सिंकियांग में आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। लेकिन ह्यूमन राइट्स वाच और एमेनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया है कि यह सब अहिंसक उइगुरों को निशाना बनाने के लिए था।

दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि बुश प्रशासन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के इस चीनी संस्करण का समर्थन किया है। इस महीने न्याय विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों ने पूछताछ करने वाले चीनी अधिकारियों के कहने पर गुआंटानामो खाड़ी में बंद उइगुरों को गंभीर यातनाएं दीं। चीनी पूछताछ अधिकारियों को आमंत्रित करने से ठीक पहले अमेरिकी सैनिकों ने उइगुरों को भूखा रखा गया और रातभर उन्हें सोने नहीं दिया।

यह एक घृणित काम है। हमें चीन का गंदा काम नहीं करना चाहिए। बुश प्रशासन आतंक के खिलाफ इस तरह के युद्ध की इजाजत देकर हमारी नैतिकता को कलंकित कर रहा है। हमने हाल के वर्षों में आतंकवादियों और अहिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच के फर्क को स्पष्ट करने की बजाए उसे मिटाने में चीन की मदद की है। ओलंपिक के दौरान आतंकवाद का सचमुच खतरा है, लेकिन उसके कारण हमें अपे सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए।

फोटो : विजय क्रान्ति

दिल्ली में जंतर मंतर पर तिब्बती प्रदर्शन : कुपात्र को ओलंपिक क्यों ?

तिब्बत समर्थक कार्यकर्ताओं की ओलम्पिक के दौरान विश्वव्यापी प्रदर्शनों की अपील

स्टुडेंट्स फॉर ए फ्री टिबेट ने बीजिंग में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी

एथेंस (ग्रीस) तिब्बत समर्थक कार्यकर्ताओं ने बीजिंग ओलम्पिक के दौरान विश्वव्यापी प्रदर्शनों का वादा किया है और कहा है कि वे बीजिंग में भी प्रदर्शन करने के लिए सुरक्षा घेरे को भेदने का प्रयास करेंगे।

छात्र आंदोलनकारियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 'स्टुडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' तिब्बत में चीनी सुरक्षा शिकंजा कसे जाने के विरोध में 8 से 24 अगस्त तक होने वाले ओलम्पिक खेलों के दौरान पूरी दुनिया में प्रदर्शन करेगा, जिसमें संभवतः बीजिंग भी शामिल होगा। यह जानकारी नेटवर्क की प्रवक्ता ल्हाडोन टेथोंग ने दी।

सुश्री टेथोंग ने तिब्बत से होकर ओलम्पिक मशाल ले जाए जाने के कार्यक्रम को निरस्त करने और तिब्बती इलाकों में मीडियाकर्मियों की स्वतंत्र पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी (आईओसी) से भी अपील की है।

वह एथेंस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं, जहां 2016 के ओलम्पिक खेलों की मेजबानी की दौड़ में शामिल शहरों के चयन के लिए आईओसी के कार्यकारी बोर्ड की तीन–दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है।

ओलम्पिक मशाल के मार्ग में तमाम प्रदर्शनों को अंजाम तक पहुंचाने वाले इस समूह के लिए बीजिंग में प्रदर्शन करना बहुत ही कठिन होगा। हालांकि सुश्री टेथोंग ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी कि यह समूह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर कैसे

ओलम्पिक मशाल के मार्ग में तमाम प्रदर्शनों को अंजाम तक पहुंचाने वाले इस समूह के लिए बीजिंग में प्रदर्शन करना बहुत ही कठिन होगा। सुश्री टेथोंग ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी कि यह समूह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर कैसे प्रदर्शन करेगा।

फोटो : विजय क्रान्ति

दिल्ली में तिब्बती भिक्षु प्रदर्शनकारी : आजादी की लड़ाई

बीजिंग ओलम्पिक के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए जारी कानूनों की सूची में वैसे कारणों की लंबी सूची है जिसके आधार पर उन्हें चीन में घुसने से रोका जा सकता है। इस सूची में टीबी या एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों, दूसरे सैक्स संबंधी रोगों, मानसिक बीमारी और वेश्याओं के साथ–साथ राजनीतिक इरादे वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।

प्रदर्शन करेगा।

चीन सरकार ने ओलम्पिक खेलों के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने की घोषणा की है। इसमें स्वयंसेवकों के रूप में अंडरकवर एजेंट भी शामिल होंगे। चीन सरकार ने विदेशियों के वीजा और रिहाइशी परमिट पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया है। विदेशियों का तिब्बत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हांगकांग में विपक्षी सांसदों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि वहां के अधिकारी भी ओलम्पिक घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शनों पर उसी तरह का प्रतिबंध लगा सकते हैं जैसे चीन में लगाए जा रहे हैं। घुड़सवारी प्रतियोगिता हांगकांग में आयोजित होगी। यह क्षेत्र प्रदर्शनकारियों को आकृष्ट कर सकता है क्योंकि यहां के कानूनों में प्रदर्शनों की छूट है।

राजनीतिक पर्यटकों पर रोक, लेकिन पालतू जानवर ले जाने की छूट

रिचर्ड स्पेन्सर, द टेलीग्राफ से साभार

बीजिंग चीन ने बीजिंग ओलम्पिक का लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचने वाले खेलप्रेमियों को चेतावनी दी है कि यदि वे राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेते हैं या कोई निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बगैर किसी सुनवाई के जुर्माना किया जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है।

बीजिंग ओलम्पिक के लिए यहां आने वाले पर्यटकों के लिए जारी कानूनों की सूची में वैसे कारणों की लंबी फेहरिस्त है जिसके आधार पर उन्हें चीन में घुसने से रोका जा सकता है। इस सूची में टीबी या एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों, दूसरे सैक्स संबंधी रोगों, मानसिक बीमारी और वेश्याओं के साथ–साथ राजनीतिक इरादे वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। लेकिन चीन सरकार ने नरमी दिखाते हुए इस बात की छूट दी है कि यात्रियों को अपने साथ एक पालतू जानवर लाने की छूट होगी।

चीनी कानूनों के अनुसार चीन की राजनीति, संस्कृति, नैतिकता और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने वाली पाठ्यसामग्रियों से युक्त किताबें, लेख और कम्प्यूटर फाइलें भी प्रतिबंधित होंगी। चीन सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिक से अधिक सजा दी जाएगी। कानूनों अनुसार, ''किसी भी तरह का गैर–कानूनी जमावड़ा, प्रदर्शन एवं आदेशों के मानने से इनकार करने पर प्रशासकीय सजा दी जा सकती है या आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है।''

प्रशासकीय सजा वह है, जो पुलिस द्वारा दी जाती है और इसके लिए उसे अदालत जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें जुर्माना भी किया जा सकता है, पुलिस अधिकतम चार वर्षों तक कैद में रख सकती है। ओलम्पिक शुरू होने से पहले ही चीनी तंत्र ने विदेशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नये वीजा प्रतिबंधों का लगाया जाना, आवासीय परमिट की जांच तथा विदेशी संगीत कार्यक्रमों और उत्सवों को रद्द किया जाना इन्हीं प्रतिबंधों की कड़ी हैं।

सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक वरिष्ठ चीनी नेता ने पिछले दिनों बताया कि ओलम्पिक खेलों के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का कारण है। उसने आतंकवादी हमलों का जोखिम बढ़ने के प्रति भी आगाह किया है। खेल स्थलों पर जिन चीजों पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रेफरियों या खिलाड़ियों पर हमले करना, पटाखे चलाना, किसी के खिलाफ बैनर थामना और धूम्रपान करना शामिल हैं।

हाल के वर्षों में ज्यादातर विदेशी 'फ्री तिब्बत' के बैनर लहराने जैसे राजनीतिक अपराधों के दोषी पाये जाने के बाद प्रत्यर्पित किये गये हैं। लेकिन विदेशियों को यह भी मालूम है कि यदि वे सरकारी आदेशों के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बिना किसी मुकदमा के जेल में भी ठूंसा जा सकता है।

चीनी सरकार ने यह भी आगाह किया है कि विदेशियों का चीन में सड़क–पार्क में सोना गैर–कानूनी है। यह अलग बात है कि बीजिंग में स्टेडियम आदि बनाने के कारण बेघर हुए हजारों लोग आजकल उपनगरों में सड़कों पर सो रह हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि टिकट खरीद लेने मात्र से ही काई दर्शक वीजा के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाएगा।

बीजिंग ओलंपिक की गोपनीयता ने चिंता पैदा की

चीन ने बीजिंग ओलंपिक के हर चरण, यहां तक टिकटों पर भी निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोहों के टिकटों में एक खास किस्म की माइक्रोचिप लगी हुई है जिसमें धारक का फोटोग्राफ, उसके पासपोर्ट का ब्यौरा, पता, ईमेल और टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। इससे ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के साथ उसे तुरंत खोजा जा सकेगा जो आयोजकों की नजर में अवांछनीय है। यह कदम ओलंपिक के इतिहास में अभूतपूर्व है।

इस कदम का मकसद 91,000 सीटों वाले नेशनल स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोहों से संभावित विरोधियों को दूर रखना है। चीन की निरंकुश सरकार को आतंकवादियों का भय तो है ही, उसे यह भी आशंका है कि तिब्बत की आजादी के समर्थक स्टेडियम में तिब्बती झंडे, चीन विरोधी बैनर या राजनैतिक संदेशों वाले टीशर्ट लहरा सकते हैं।

उद्घाटन समारोह, जो 8 अगस्त को होगा, के टिकट सबसे महंगे हैं। इन टिकटों को ज्यादातर बड़ी हस्तियों और उनके दोस्तों ने खरीदा है। सबसे अधिक मंहगे टिकट की कीमत 720 अमेरिकी डॉलर है। माइक्रोचिप पर इस तरह के व्यक्तिगत ब्यौरों से गोपनीयता और संभावित आइडी की चोरी के बारे में चिंता पैदा हो गई है। इसके अलावा, उद्घाटन के दिन अराजकता का भी खतरा पैदा हो गया है क्योंकि अधिकारियों को टिकटों का मिलान उनके ध ाारकों से करने में समय लगेगा। जाहिर है, चीन के इस कदम से उसके बारे में खराब संदेश जा रहा है।

एक ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा विशेषज्ञ रोजनर क्लार्क ने कहा, ''चीन के अधिकारियों को टिकटधरियों की पहचान के बारे में चिंता करने के बजाए खतरनाक उपद्रवियों को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए।'' क्लार्क की कैनबरा स्थित एक्समैक्स कंसल्टैंसी ऑनलाइन सुरक्षा और पहचान प्रमाणीकरण के बारे में परामर्श देती है। उन्होंने आगे कहा, ''अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाना चाहता है, कोई व्यक्ति बम फेंकना चाहता है या कोई व्यक्ति तिब्बती झंडा लहराना चाहता है तो उसकी पहचान उसके परिचयपत्र से नहीं की जाती। वे अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए अपने साथ ऐसी सामग्री लेकर चलते हैं। चीन को इस तरह की सामग्री को पहचानने और इसे जब्त करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

तिब्बती लेखिका पर साइबर हमला

वोज़ेर की वेबसाइट हैक करके उनके खिलाफ चीनी हैकरों का घृणा अभियान

रायटर समाचार एजेंसी के अनुसार तिब्बत में अशांति पर लिखने वाली एक तिब्बती असंतुष्ट लेखिका वोज़ेर को चुप करने के लिए उन पर साइबर हमला किया जा रहा है। उनके परिचितों को भी धमकियां दी जा रही हैं। वोज़ेर के चीनी पति वांग लिजिओंग ने रायटर को बताया कि हैकरों ने उनकी पत्नी की स्काइप (इंटरनेट टेलीफोन) आइडी चुरा ली और वे उनके 170 से अधिक संपर्कों को धमका रहे हैं। हैकरों का उद्देश्य राजनैतिक सूचनाएं हासिल करके इन्हें उन्हीं के खिलाफ आरोप लगाने में करना है। अधिकारियों ने पिछले दो वर्षा में चीनी सर्वर पर वूसर के तीन लॉग बंद कर दिए।

वांग ने फोन पर रायटर को बताया, ''यह वोज़ेर के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उसके दोस्तों के लिए उससे भी बड़ा खतरा है।'' वांग 1990 के दशक के बेस्टसेलर पुस्तक ''येलो पेरिल'' के लेखक हैं।

न्यूयार्क स्थित स्टुडेंट्स फॉर ए फ्री टिबेट की प्रचार निदेशक केट वोजनाउ ने वोज़ेर को चीन में तिब्बतियों के बीच 'एकमात्र आवाज' बताया है। वोज़ेर ने तिब्बत में हाल की अशांति पर काफी कुछ लिखा है जिसके कारण चीनी सरकार उन पर कुपित है। हैकरों ने वूसर के ब्लॉग वोज़ेर मिडिल वे. नेट को भी हाइजैक कर लिया और उसकी सामग्री को उड़ाकर चीन के लहराते हुए पांच सितारा राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर डाल दी। चीनी राष्ट्रवादी हैकरों के एक समूह रेड हैकर्स एलायंस ने साइबर हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है।

हैकरों ने वूसर के लॉग पर उनकी एक तस्वीर भी डाली जिसे उन्होंने उनके कंप्यूटर से चुराया था। तस्वीर का शीर्षक था : ''कृपया नीचे दिए तिब्बती अलगाववादी वोज़ेर का बदबूदार चेहरा याद रखें। वूसर को जो भी देखे वह उसे उसी तरह पीटे जिस तरह पानी में कुत्तों को पीटा जाता है।''

न्यूयॉर्क स्थित वाचडॉग कमेटी टू प्रोटेक्ट जॅर्नलिस्ट्स के एशिया प्रोग्राम संयोजक बॉब दिएत्स ने एक बयान में कहा, ''यह चिंताजनक घटना है। वूसर एक सशक्त स्वतंत्र आवाज हैं जिनके चीन के तिब्बती क्षेत्रों में ढेरों संपर्क हैं। उनकी साइट को इस तरह से हैक कर लेना यही दर्शाता है कि तिब्बतियों को तिब्बत के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।''

चीनी हैकरों ने वूसर के ब्लॉग वोज़ेर मिडिल वे. नेट को भी हाइजैक कर लिया और उसकी सामग्री को उड़ाकर चीन के लहराते हुए पांच सितारा राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर डाल दी। हैकरों ने वूसर के लॉग पर उनकी एक तस्वीर भी डाली जिसे उन्होंने उनके कंप्यूटर से चुराया था। तस्वीर का शीर्षक था : ''कृपया नीचे दिए तिब्बती अलगाववादी वोज़ेर का बदबूदार चेहरा याद रखें। वूसर को जो भी देखे वह उसे उसी तरह पीटे जिस तरह पानी में कुत्तों को पीटा जाता है।''

फोटो : विजय क्रान्ति

तिब्बत में चीनी अत्याचारों का मंचन करते प्रदर्शनकारी : चीन की असलियत

तिब्बत में निर्मम हत्याओं पर आईसीटी का संयुक्त राष्ट्र में बयान

निष्पक्ष प्रेक्षकों के बिना सं रा की रिपोर्ट पर आपत्ति

हमने यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि पिछले दो महीनों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सुरक्षाकर्मियों की सख्त से सख्त कार्रवाई में 200 से अधिक तिब्बतियों के मारे जाने के साथ ही तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति में और अधिक गिरावट दर्ज की गयी है।

जेनेवा तिब्बतियों के मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक आजादी को संरक्षित करने में जुटे संगठन इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर टिबेट (आईसीटी) ने तिब्बत में न्यायेतर और उचित सुनवाइयों के बगैर दी गयी सजाओं को लेकर गत तीन जून को जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में मौखिक बयान दिया। चूंकि आईसीटी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए यह बयान फ्रांस लिबर्टीज के नाम से जारी किया गया।

आईसीटी ने हाल के दिनों में तिब्बत में चीनी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों को गोली का शिकार बनाये जाने एवं सितम्बर 2006 में नांगपा दर्रे के पास केलसांग नामत्सो नामक 17 वर्षीया भिक्षुणी की हत्या पर चीन सरकार के उदासीन रवैये को लेकर चिंता जताई है।

उन्होंने कहा, ''अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि पिछले दो महीनों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सुरक्षाकर्मियों की सख्त से सख्त कार्रवाई में 200 से अधिक तिब्बतियों के मारे जाने के साथ ही तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति में और अधिक गिरावट दर्ज की गयी है।''

बयान में पूछा गया है, ''स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं की गैर–मौजूदगी में चीन से तिब्बतियों की हत्यों से संबंधित अनेक रिपोर्टों पर आखिर किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है?'' यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ की ओर से तैयार की गयी है, जिसे मामलों की जांच करने और उन सरकारों से सीधे आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बिना ही सजा देने या घातक बल प्रयोग की विश्वसनीय खबरें हों।

अपने खिलाफ चीन के दुष्प्रचार से दलाई लामा दुखी

दलाई लामा ने 25 मई को कहा कि वे बीजिंग के उस दुश्प्रचार से दुखी हैं जिसमें कई चीनियों के दिमाग में उनकी छवि 'सींगों वाले शैतान' जैसी बनाने की कोशिश की जा रही है।

निर्वासित तिब्बती शासक और आध्यात्मिक नेता ने नॉटिंघम (मध्य इंग्लैंड) में पांच दिवसीय वार्ताओं और व्याख्यानों के पहले दिन कहा कि प्रचार तंत्र पर बीजिंग के नियंत्रण के कारण लाखों चीनी उन्हें 'पिशाच' मानते हैं। उन्होंने नॉटिंघम एरेना में एक वार्ता में कहा, ''आधुनिक चीन में भावात्मक मानव मूल्यों का अभाव है...लाखों निरीह चीनियों के पास सरकारी प्रोपेगैंडा के अलावा सूचना पाने का और कोई साधन नहीं है। यदि लाखों लोग यह सोचते हैं कि दलाई लामा 'पिशाच' हैं तो मुझे दुख ही होगा। इससे समस्याओं के समाधान में कोई मदद नहीं मिलेगी। हिंसक उपायों से सचाई को दबाया नहीं जा सकता। हिंसक दमन से सचाई और मजबूत बनकर उभरती हैं।

दलाई लामा ने कहा : तावांग भारत का हिस्सा है

नयी दिल्ली, 04 जून (टाइम्स ऑफ इंडिया) इतने वर्षों में पहली बार तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन भले ही दावा करे, लेकिन यह भारत का हिस्सा है।

नवभारत टाइम्स को दिये साक्षात्कार के दौरान दलाई लामा ने 1914 के शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन लाइन की वैधता की चर्चा करते हुए कहा कि तिब्बत और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है।

वर्ष 2003 में तवांग की यात्रा के वक्त दलाई लामा से इस मुद्दे पर टिप्पणी करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसका सीधा उत्तर नहीं दिया था कि अरुणाचल प्रदेश एक समय तिब्बत का अंग था। चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और उसका दावा है कि तवांग एवं अरुणाचल

प्रदेश उसके सीमा क्षेत्र में आता है।

इस बयान का भारत–चीन बातचीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि चीन ने पहले ही कह रखा है कि यदि उसे तावांग सौंप दिया जाता है तो वह शेष अरुणाचल प्रदेश से अपना दावा छोड़ देगा।

रणनीतिक तौर पर चीन का यह प्रस्ताव भारत को अस्वीकार्य है, क्योंकि तावांग न केवल पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा है, बल्कि भूटान से भी जुड़ा है। तावांग बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल भी है, क्योंकि यहां छठे दलाई लामा पैदा हुए थे।

तिब्बत में हान लोगों की व्यापक बस्तियों के बारे में पूछे जाने पर दलाई लामा ने कहा कि ल्हासा की आबादी का दो–तिहाई हिस्सा हान समुदाय के लोग हैं। लेकिन तिब्बत में अभी भी तिब्बती बहुलता में हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि चीन सरकार उनके दावे पर विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा, ''समूची दुनिया जानती है कि हम चीन से अलग होना नहीं चाहते। हम केवल यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और धार्मिक पहचान बरकरार रहे। तिब्बत विशेष क्षेत्र के रूप में पहचाना जाए, हम केवल यही चाहते हैं।''

प्रो. सामदोंग रिंपोछे का 'तिब्बत के भविष्य की संभावनाओं' पर व्याख्यान

तेन्जिन सांगमो, फायुल से साभार

नयी दिल्ली, 16 जून भूटान में भारत के पूर्व राजदूत दिलीप मेहता की अध्यक्षता में टिबेटन पार्लियामेंट्री एंड पॉलिसी रिसर्च सेंटर के के सहयोग से 'तिब्बत में भविष्य की संभावनाओं' पर आज गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।

तिब्बत के प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिम्पोछे ने इस अवसर पर उपस्थित आगंतुकों को सम्बोधित करते हुए सातवीं सदी में तिब्बत और भारत के ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि तिब्बती भाषा की अपनी लिपि है, जिसकी व्युत्पत्ति प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि से हुई है और यह भारतीय भाषाओं के परिवार से जुड़ी है।

दलाई लामा पदवी का मूल सोनाम ग्यात्सो में है जिन्हें 1578 में दलाई लामा की उपाधि दी गयी थी। वह ल्हासा के गांदेन फोटांग सरकार के प्रमुख एवं तीसरे दलाई लामा थे। तिब्बती संघर्ष की प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा, ''तिब्बती संघर्ष की प्रकृति सत्य और झूठ, न्याय और अन्याय एवं किसी व्यक्ति के कर्तव्यों पर अमल के रुख में अंतर के रूप में है। हम सार्वभौमिक जिम्मेदारी के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं।''

चीन के संविधान से स्वायत्तता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा, ''हम संविधान के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगें चीन के चार्टर के अनुसार ही हैं।''

राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और भाषाई विविधता एवं चीन के भी 55 अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करना है। दलाई लामा और तिब्बती केंद्रीय प्रशासन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन से अलग करने की मांग नहीं करता है, बल्कि यह मांग करता है कि चूंकि टीएआर के निवासियों की राष्ट्रीयता अलग है, इसलिए उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। सिद्धांततः यह संभव होना चाहिए क्योंकि यह चीन के संविधान के तहत ही है।

इस अवसर पर उपस्थित भारतीय वक्ताओं ने भी इस बात से सहमति जताई कि तिब्बत का हित न केवल तिब्बतियों के साथ है बल्कि भारत और उसकी सीमा की सुरक्षा में भी है। तिब्बत की समस्या से भारत खुद को अलग नहीं रख सकता है क्योंकि तिब्बत का मसला भी भारत के हितों से जुड़ा हुआ है।

तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय राजनीतिज्ञों से मिला

धर्मशाला, 02 जून तिब्बती निर्वासन संसद का एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी स्पीकर दोल्मा ग्यारी के नेतृत्व में 12 से 25 मई तक नयी दिल्ली में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के 37 नेताओं से मुलाकात की, जिनमें सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी, शरद पवार, जार्ज फर्नांडीस, शरद यादव, अजीत सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह शामिल हैं।

सुश्री दोल्मा ग्यारी ने कहा, ''हमारी समस्याओं के प्रति भारतीय नेताओं ने जो समर्थन और चिंता प्रकट की उससे हम काफी उत्साहित हैं। ज्यादातर ने दलाई लामा की अहिंसक नीति का समर्थन किया।''

प्रतिनिधिमंडल ने सं. राष्ट्र के नई दिल्ली कार्यालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की। परमपावन दलाई लामा के नयी दिल्ली स्थित ब्यूरो ने बैठक का समन्वय किया था। प्रतिनिधिमंडल में सुश्री दोल्मा ग्यारी के अलावा निर्वासन संसद के सदस्य भिक्षु सोनम तेनफेल, सुश्री दोल्कर ल्हामो कीर्ति और सुश्री दोल्मा त्सेरिंग शामिल थे।

तिब्बती संघर्ष की प्रकृति सत्य और झूठ, न्याय और अन्याय एवं किसी व्यक्ति के कर्तव्यों पर अमल के रुख में अंतर के रूप में है। हम सार्वभौमिक जिम्मेदारी के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'' चीन के संविधान से स्वायत्तता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा, ''हम संविधान के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगें चीन के चार्टर के अनुसार ही हैं।

तिब्बत मुक्ति–साधना का तूफान पूरे तिब्बत में फैला, दुनिया की आंखें खुलीं

10 मार्च, से तिब्बत में उठी जनक्रान्ति और चीनी दमन का तिथिवार विवरण–4

24 मार्च, 2008

सिचुआन प्रांत की **द्राकगो काउंटी** के तहत **चोकरी गांव** में 24 मार्च को न्गांगखोंग भिक्षुणी मठ की 200 भिक्षुणिओं और स्थानीय लोगों ने तेहोर टाउनशिप के सरकारी मुख्यालय तक मार्च किया। इनके साथ **चोकरी मठ** के 200 भिक्षु और **खासुम** मठ की 150 भिक्षुणिआं भी शामिल हो गयीं। चीनी सेना की गोलीबारी में चोकरी मठ का एक 21–वर्षीय भिक्षु मारा गया। एक और प्रदर्शनकारी त्सेवांग धोंदुप की किडनी में गोली लगी है और बचने की संभावना बहुत ही क्षीण है।

चीन सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी पत्रकारों का दल जब सुगलाखांग मंदिर की यात्रा कर रहा था उस वक्त कुछ भिक्षु विदेशी मीडिया के सामने अचानक जा पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया कि तिब्बत में धार्मिक आजादी नहीं है। इन भिक्षुओं की इस साहसिक कार्रवाई ने चीन सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया।

25 मार्च, 2008

तिब्बत में हाल के प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मठों – सेरा, द्रेपुंग और गंदेन में चीनी सेना और पीएपी के जवानों ने पानी, बिजली, खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुविधाओं को रोक दिया है। खाने–पीने के सामान की कमी, बाहर निकलने पर प्रतिबंध।

चिंघाई प्रांत की **थांग काउंटी** में **होल्खा** टाऊनशिप के सैकड़ों तिब्बती नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन के मुख्यालय पर करीब साढ़े दस बजे प्रदर्शन शुरू किया और यह अपराह्न एक बजे तक चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान एक बैनर पर चीनी भाषा में लिखा था, ''तिब्बत में दमन और उत्पीड़न पर रोक लगाओ।''

सिचुआन प्रांत की **लिथांग** काउंटी में एक सरकारी कार्यालय में आग लगा दी गयी। स्थानीय तिब्बती नागरिकों का मानना है कि यह काम खुद चीनी अधिकारियों का है, जो ऐसी हरकत कर तिब्बतियों की छवि धूमिल करना चाहते हैं।

26 मार्च, 2008

ल्हासा में कड़े प्रतिबंधों का सिलसिला जारी रहा। चीनी सेना ने **त्सुगलांखांग मंदिर** और **बारखोर** में अपना शिकंजा और कस दिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।

चीनी अधिकारियों ने **सिचुआन** प्रांत में **कारजे** स्थित **चोकरी मठ** के भिक्षुओं को मठ छोड़ने के निर्देश दिये हैं। नांगगोंग भिक्षुणी मठ की भिक्षुणिओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है।

द्राकगो काउंटी स्थित मठों और मकानों में चीनी सैनिकों का तलाशी अभियान जारी है। अनेक भिक्षुओं और स्थानीय नागरिकों के ठौर–ठिकाने ज्ञात नहीं हैं। चीनी सुरक्षाकर्मियों की गोली से मारे गये **चोकरी मठ** के भिक्षु कूंगा की आत्मा की शांति के लिए जब भिक्षुओं ने प्रार्थना सभा आयोजित की तो उसमें स्थानीय लोग भी जुड़ गये। सैनिकों द्वारा बंदूकें तानने पर भिक्षुओं और आम नागरिकों ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया।

चिंघाई प्रांत की **गेपा सुमदो** काउंटी स्थित **सेरलेक मठ** के भिक्षुओं ने भी चीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इसी प्रांत की **द्राकगो काउंटी** में 24 और 25 मार्च की सफलतापूर्वक किये गये विरोध प्रदर्शनों के बाद चीनी अधिकारियों ने कम से कम 20 मोटरसाइकिलें जब्त की। इसका सीधा मतलब प्रदर्शनकारियों के इधर–उधर जाने पर प्रतिबंध लगाना और गिरफ्तारी से बचने के उनके प्रयासों पर विराम लगाना है। **सिचुआन प्रांत** की **दार्त्सेदो काउंटी** में तिब्बतियों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

सिचुआन प्रांत की **नाग्चू काउंटी** स्थित **मीन्याक** शहर में चीन की करेंसी पर तरह–तरह के नारे लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया। आंदोलनकारी करेंसी नोटों पर 'तिब्बत एक स्वतंत्र देश है' लिखकर उसे इधर उधर बिखेरने लगे। (चीन में 50 पैसे और उससे भी छोटे नोटों का प्रचलन है – संपादक)

27 मार्च, 2008

चीन सरकार द्वारा प्रायोजित विदेशी पत्रकारों का दल जब **सुगलाखांग मंदिर** की यात्रा कर रहा था उस वक्त कुछ भिक्षु विदेशी मीडिया के सामने अचानक जा पहुंचे और उन्होंने विदेशी पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया कि तिब्बत में धार्मिक आजादी नहीं है। इससे पहले चीनी प्रशासन ने सभी भिक्षुओं को मंदिर में आने वाले विदेशियों से दूर रहने का निर्देश दिया था। इन भिक्षुओं की इस साहसिक कार्रवाई ने चीन सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बाद में इन भिक्षुओं को यह बयान देते हुए दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखाया गया।

26 मार्च को **त्सेगोर थांग काउंटी** में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गयी एक युवती और रिबुनग्याल नामक एक युवक की रिहाई की मांग के समर्थन में मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ।